



प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूँज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार



देश का
उद्धार
विलासियों
द्वारा नहीं
हो सकता उसके लिए
सच्चा त्यागी होना
पड़ेगा।
गुंथी प्रेमचंद

वर्ष-03, अंक - 40

(साप्ताहिक)

खवासा, गुरुवार 08 जुलाई 2021

पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

म.प्र. के नए राज्यपाल होंगे श्री पटेल

भोपाल। गुजरात के वरिष्ठ भाजपा नेता मंगूभाई छानभाई पटेल को मध्यप्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास मध्यप्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार था। उधर, मध्यप्रदेश से राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक के राज्यपाल के तौर पर नई जिम्मेदारी दी गई है। मंगूभाई और थावरचंद के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। इनके पहले आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ मध्यप्रदेश के राज्यपाल पद पर थीं। मध्यप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर मंगूभाई पटेल ने कहा कि, मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभारी हूँ। नरेंद्र मोदी के हम पहले से साथी थे, उन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया उस पर हम चलते रहे और समाज सेवा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।



केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के हटने के बाद अब म.प्र. के मंत्री चौधरी पर भी गिर सकती है गाज

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के लोकप्रिय नेता हर्षवर्धन को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि, कोरोना का दूसरी लहर के दौरान खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें हटाया गया। इसके बाद मध्यप्रदेश में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पर इस्तीफे का दबाव बढ़ जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में ज़ाह-ज़ाह के हालात थे। हर दिन संक्रमण और संक्रमित नागरिकों की मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। हालात को गंभीरता बताने के लिए श्मशान घाट और विश्राम घाटों के फोटो जारी किए जा रहे थे। लोग स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे थे, परंतु स्वास्थ्य मंत्री कंट्रोल रूम में नहीं थे।

सारे कयासों पर विराम: मोदी मंत्री मंडल का हुआ विस्तार, 12 ने दिए इस्तीफे, 43 मंत्री ने ली शपथ

ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हुए मोदी की कैबिनेट में शामिल



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार से पहले 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, इसमें दिगंज मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डॉ हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, संतोष गंगवार केंद्रीय श्रम मंत्रालय, रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, रतनलाल कटारिया, संजय धोत्रे राज्य मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, देवेंद्र



अनपूर्णा देवी, ए नारायणस्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, बीएल वर्मा, भगवत कृष्णकाव कराद, राजकुमार रंजन सिंह, भारतीय प्रवृत्ति पवार, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतिभा भौमिक, शोभा करंदलाजे, महेंद्रभाई मुंजापारा, अजय कुमार, देव सिंह चौहान, भगवंत खुवा, विश्वेश्वर टुडू, शांतनु ठाकुर, सुभाष सरकार, जॉन बलॉ ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। वहीं नारायण तनु राणे, सर्वानंद सोनोवाल, डॉ. वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हर्दीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, पशुपति पारस, जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। उक्त मंत्री मंडल को लेकर कई दिनों से अपने-अपने कयास लगाए जा रहे थे, जो बुधवार को सारे कयासों पर विराम होकर, केंद्रीय मंत्री मंडल का विस्तार किया गया। बता दें कि, मोदी ने अपने मंत्री मंडल के विस्तार के पूर्व, प्रधानमंत्री आवास पर अपने कैबिनेट मंत्री व शपथ लेने वाले मंत्रियों की बैठक लेकर विस्तार से चर्चा होने के बाद हनु तुरंत काम पर लौटे, साथ ही हार्ड कोर्ट ने राज्य सरकार को भी आदेश दिए हैं कि, नरेंद्र मोदी के जो मांगे हैं उसके लिए भी कमेटी गठित कर उसका एक महीने में निराकरण करें।

7 हुए प्रमोटेड, 28 राज्य मंत्री, 15 कैबिनेट मंत्री ने ली शपथ

एल मुरगन, पंकज चौधरी, अनुप्रिया सिंह पटेल, सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, नीतीश प्रमाणिक, भानुप्रताप सिंह धोत्रे राज्य मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, देवेंद्र

जज पर सवाल उठाने के मामले में ममता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना



कोलकाता, एजेन्सी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने जज पर सवाल उठाने के मामले में 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंदा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार पाते हुए पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन पैसों का इस्तेमाल कोविड-19 से पीड़ित परिवारों के सदस्यों की मदद में किया जाएगा। बता दें कि, ममता बेनर्जी ने नंदीग्राम में हार के बाद अदालत में दायर याचिका की सुनवाई के लिए जज बदलने की मांग की थी।

कोलकाता हाई कोर्ट के जज कौशिक चंदा नंदीग्राम विधानसभा सीट से भाजपा के शुभेंद्रु अधिकारी को निर्वाचन को चुनौती देने वाली ममता बेनर्जी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। न्यायमूर्ति चंदा ने अर्जी पर 24 जून को फेसलाफ सुनिश्चित रखा था कि, उनकी चुनाव याचिका पर सुनवाई से न्यायाधीश को खुद को अलग रखना चाहिए, मामला अब किसी दूसरी पीठ को सौंपने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को भेजा जाएगा। न्यायमूर्ति चंदा ने कहा था कि, वह भाजपा के विधिक प्रकोष्ठ के संयोजक कभी नहीं रहे, लेकिन पार्टी की ओर से अनेक मामलों में कोलकाता हाई कोर्ट में पेश हुए थे।

चारधाम यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही आईआरसीटीसी



नई दिल्ली, एजेन्सी। देश भर में कोरोना वायरस के घटते मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने सितंबर में चार धाम यात्रा संचालित करने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन-बद्रीनाथ, जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश सहित कई शीर्ष पर्यटन स्थलों की सैर कराएगी। रामायण सर्किट पर संचालित होने वाली 'श्री रामायण यात्रा' ट्रेन की लोकप्रियता और सफलता के बाद आईआरसीटीसी ने अब 'देवो अपना देश' के तहत चार धाम यात्रा के लिए डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है।

प्रेस विज्ञापि अनुसार, 16 दिनों की यह यात्रा 18 सितंबर, 2021 को दिल्ली के सफ्दरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी और बद्रीनाथ की यात्रा कराएगी, जिसमें माना गांव (चीन सीमा के पास), नरसिंह मंदिर (जोशीमठ), ऋषिकेश, जगन्नाथ पुरी सहित पुरी का गोल्डन बीच, कोणार्क का सूर्य मंदिर, चंद्रभागा समुद्र तट, धनुषकोडी सहित रामेश्वरम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश, शिवराजपुर समुद्र तट और बेट द्वारका शामिल है। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु करीब 8 हजार 5 सौ किलोमीटर का सफर तय करेंगे। स्टेट ऑफ आर्ट डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। ट्रेन में दो बडिया डार्निंग रैस्तरा, एक आधुनिक किचन, कोचों में शॉवर वयूबिकल्स, सेंसर-आधारित वॉशरूम फंक्शन, पुर मसाजर सहित कई विशेषताएं हैं। पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन दो प्रकार के आवास प्रदान करती है - परस्ट एसी और सेकंड एसी। ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। ट्रेन के प्रत्येक कोच में सीसीटीवी कैमरों के अलावा सुरक्षा गार्ड को तैनात किए गया है।

नर्सिस की हड़ताल अवैध, जल्द काम पर लोटे - हाई कोर्ट



जबलपुर। मध्यप्रदेश में पिछले 8 दिनों से जारी नर्सिस की हड़ताल को हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। नर्सिस हड़ताल के खिलाफ लगी जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि, सभी नर्सिस अपनी हड़ताल को खत्म करते हुए तुरंत काम पर लौटें, साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भी आदेश दिए हैं कि, नर्सिस की जो मांगे हैं उसके लिए भी कमेटी गठित कर उसका एक महीने में निराकरण करें।

नागरिक उपभोक्ता मंच ने लगाई थी याचिका कोरोना संक्रमण काल में अपनी मांगों को लेकर नर्सिस का हड़ताल पर जाना जनहित को देखते हुए ठीक नहीं है। लिहाजा इसको देखते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हड़ताल पर बैठी प्रदेश भर की नर्सिस को काम पर वापस जाने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि, मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए पहले ही डॉक्टरों-नर्सों की सेवा को अति आवश्यक बताया था, इसके बाद भी नर्सिस हड़ताल पर चली गईं। हाई कोर्ट ने जहाँ कोरोना काल में नर्सिस की सेवा को अति आवश्यक मानते हुए वापस काम पर लौटने के आदेश दिए हैं। वहीं राज्य सरकार से भी कहा है कि, नर्सिस ने जितने भी दिन काम बंद कर हड़ताल की है उसका वेतन न रोके।

वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने से घट जाता है कोरोना से मौत का जोखिम: आईसीएमआर



नई दिल्ली। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपने ताजा अध्ययन में पाया है कि, वैक्सीन की दो खुराकें कोरोना से होने वाली मौतों को 95 फीसदी तक कम करती हैं, तो वहीं सिंगल डोज लेने वालों में मौत का जोखिम 82 फीसदी तक घट जाता है। यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में छपा है। अध्ययन तमिलनाडु पुलिस विभाग में काम करने वाले उन 1 लाख 17 हजार 524 कर्मियों पर किया गया है, जो वैक्सीन की एक या दोनों डोज ले चुके हैं।

शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में बताया है, हमारे अध्ययन में यह संकेत मिलते हैं कि भले ही वैक्सीन की एक ही खुराक क्यों न ली गई हो, उससे कोरोना मौतों कम होती हैं। कोरोना से होने वाली मौतों को कम करने और भविष्य में इसकी लहरों से बचने के लिए जल्द ही बड़ी आबादी का टीकाकरण जरूरी है। तमिलनाडु पुलिस डिपार्टमेंट दूसरी लहर के दौरान अपने सभी सदस्यों के टीकाकरण और कोरोना मौतों के आंकड़ों को लेकर दस्तावेज तैयार कर रही है। इस दस्तावेज में अस्पताल में भर्ती होने की तारीख और टीकाकरण संबंधी जानकारीयें भी हैं।

दोस्ती को किया कलंकित: सहेली के साथ दुष्कर्म में बहन ने भाई का किया सहयोग

भाई-बहन के साथ तीन पर मामला दर्ज

माही की गूँज, रतला। जिले के जावरा में रहने वाली एक 25 वर्षीय विवाहिता के साथ उसकी सहेली का भाई दुष्कर्म कर रहा था। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर पीड़ित महिला से दोबारा दुष्कर्म किया और 10 हजार रुपयों की वसूली भी की। पीड़ित महिला की सहेली भी दुष्कर्म के आरोपी भाई की मदद करती थी। दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की शिकार हुई महिला ने यह बात अपने पति को बताई, जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के कांचरिया देव गांव के धारसिंह, उसकी बहन और एक अन्य आरोपी पर जावरा सिटी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। सिटी थाना पुलिस ने बताया, जावरा

विवाहित महिला की एक सहेली अपने भाई के साथ उससे मिलने आया करती थी। एक अप्रैल को सहेली का भाई धारसिंह महिला के घर पहुंचा और पति की हत्या कर देने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने पीड़िता से दोबारा दुष्कर्म किया और उससे 10 हजार रुपए की वसूली भी कर ली। पीड़िता को धमकाने और ब्लैकमेल करने में धारसिंह की बहन और एक अन्य साथी सुनील भी उसका सहयोग कर रहा था। अपनी सहेली के भाई द्वारा दुष्कर्म और सहेली से दोस्ती में धोखा खाने के बाद पीड़ित महिला ने पूरा मामला अपने पति को बताया उसके बाद मामला दर्ज करवाया। उक्त मामले में जावरा शहर थाना पुलिस ने दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धमकाने के मामले में आरोपी धारसिंह पिता तुलसीराम सोलंकी निवासी काचरिया देव थाना मल्हारगढ़ जिला

मन्दासौर, उसकी बहन और एक अन्य साथी सुनील के खिलाफ 450, 376(2)द, 376(क), 387, 506 भादवि का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

विदेश मंत्री रूस की तीन दिवसीय यात्रा पर

नई दिल्ली, एजेन्सी। एक ओर जहां पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान में तालिबान पर प्रहार करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की तीन दिन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। तेहरान के रास्ते होते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मास्को के लिए बुधवार को रवाना हुए। माना जा रहा है कि, अफगानिस्तान के घटनाक्रम ही इस दौर के मुख्य एजेंडे हैं। रूस दौर के दौरान ही विदेश मंत्री का पड़व ईरान भी होगा, जहां वह तेहरान में सरकार के साथ आधिकारिक बैठक कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि, विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के बीच वार्ता में कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई में सहयोग एवं अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श हो सकता है। सूत्रों ने यह भी बताया कि, जयशंकर के दौर का उद्देश्य वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन की तैयारी करना और अफगानिस्तान में तेजी से उभरती परिस्थितियों पर चर्चा करना है। विदेश मंत्रालय की मानें तो रूस के साथ बातचीत में कोविड-19 महामारी से लड़ाई के खिलाफ सहयोग और विभिन्न क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सात जुलाई से नौ जुलाई के दौर में जयशंकर उप प्रधानमंत्री युरी बोरीसोव से मुलाकात करेंगे जो भारत-रूस वाणिज्य, अर्थ, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी एवं सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग में उनके समकक्ष हैं। वह अंतरराष्ट्रीय मामलों पर स्टेट डूमा कमेटी के अध्यक्ष लियोनाद स्लत्स्की से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि, जयशंकर मास्को में प्रतिष्ठित प्रीमाकोव इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में 'बदलती दुनिया में भारत-रूस संबंध' पर व्याख्यान भी देंगे। भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन पिछले वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित हो गया था।



बढ़ रहे नशे के कारोबार को लेकर पुलिस कर रही ऊँट पर बैठकर बकरी चराने का काम

जिले में बर्बादी की कहानी लिख रहा नशे का कारोबार, बड़े तस्कर पुलिस की पकड़ से दूर

माही की गूँज, झाबुआ। मुजम्मिल मंसूरी

दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश हमारा भारत है, लेकिन नशाखोरी और नशे के कारोबार में फंसकर बड़ी तादाद में युवा जेलों में बंद है। नशे की लत या नशे के कारोबार ने इनके जीवन के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है और ऐसे कई परिवार बर्बादी की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यह भी सत्य है कि नशा, नाश का कारण है। किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए जरूरी नहीं कि उस पर मिसाइलें दागी जाएं। किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा शक्ति पर निर्भर करता है। यदि देश की नींव कहे जाने वाले इस युवा वर्ग को नशे की लत, लग जाए तो देश को गर्त में जाने से कोई रोक नहीं सकता। नशे का कारोबार बर्बादी की कहानी लिखने में खामोश व नशीला युद्ध का रोल अदा करने वाला अचूक हथियार है। अपराध की दुनिया से जुड़े तमाम विवादों का जन्म यहां से शुरू होता है। नशे के शौक से आभारधिक जानत का श्राफ भी बढ़ रहा है। नशे का कारोबार करने वाले नशे को मनचाहे दामों पर बेचकर कई लोगों के भविष्य को बर्बाद करके धनाढ्य बन रहे। नशे के कारोबार में लिये लोगों के पर राजनीतिक संरक्षण तो रहता ही है वहीं पुलिस का निम्नमान इन्हे रोकने की बजाय

बढ़ावा देता ही दिखाई देता है।

जिले में नशे के कारण कई युवाओं ने अपनी जान गंवाई। कई बार नशे में धुत होकर तो कहीं नशेडियों के हमले से कई घरों के चिराग बुझ गए। वहीं सांप निकलने के बाद लाठी पीटने की तर्ज पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किए और उन्हें सुलझाया भी, लेकिन पुलिस ने कभी नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने की कोशिश ही नहीं की। किया तो सिर्फ यह कि उसकी आसपास की टहनियों को काट दिया ताकि वह फिर से दुगुनी रफ्तार से फैल सके। नशे के कारोबार का यह पौधा अगर पुलिस उखाड़ना चाहती है तो इसकी जड़े उखाड़नी होंगी। जिले में फैले इस नशे के समंदर की बड़ी मछली पर हाथ डालना होगा वरना वह कहावत है कि 'ऊँट पर बैठ कर बकरी चराने का क्या फायदा...?'

पुलिस ने रविवार रात एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा। बताया जा रहा है कि यह युवक ब्राउन शुगर लेकर गुजरात में कहीं खपाने जा रहा था। पुलिस की पकड़ में



आने के बाद जब पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को बताया कि उसने यह ड्रग्स जिला मुख्यालय के समीप ग्राम मिंडल के राहुल पिता सिमोन डामोर से खरीदी है। राहुल वही सख्स है जो 12 मार्च को ब्राउन शुगर केस में पकड़ा गया था। उस समय भी पुलिस ने इसके कब्जे से करीब 40 हजार रुपये का ड्रग्स बरामद किया था। उस समय इसके साथ पुलिस तीन और लोगों को गिरफ्तार किया था जिसमें भाजपा से जुड़ी एक महिला भी शामिल थी। नशा तस्करों का यह गिरोह रत्नाम, मंदसौर, नीमच व उसके आसपास से ब्राउन शुगर लाकर यहां के युवाओं को बेचता है। पुलिस ने इन्हे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था लेकिन पिछले महीने ही राहुल को जमानत मिल गई। बाहर आने के बाद

राहुल ने फिर से अपना नशे का कारोबार शुरू कर दिया।

रविवार को पकड़ी गई ब्राउन शुगर की कीमत 50 हजार बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने जिस युवक को पकड़ा है उसका नाम शाहिद रजा निवासी राणापुर बताया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस अपनी आदत अनुसार अभी तक इसकी किसी भी बड़ी कड़ी तक नहीं पहुंच पाई है। पकड़े गए युवक ने राहुल का नाम लिया लेकिन वह भी अभी तक पुलिस गिरफ्तार से बाहर ही है। राहुल पर और भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार युवक को न्यायालय में पेश कर वहां से उसे जेल भेज दिया गया।

इसके विपरीत पिछले दो सालों में नशे के अधिक सेवन से झाबुआ शहर के तीन युवकों ने अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा नशे के कारण ही दो युवकों की हत्या भी जिला मुख्यालय पर हो चुकी है। नशे के कारण अपने बच्चों को खोने वाले माता-पिता व परिजनों के साथ कई सामाजिक

संस्थाओं के सदस्यों ने भी जिले के अलावा अधिकारियों को जिले में नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए आवेदन के साथ अनुनय विनय किए। उन्हें आश्वासन भी दिए गए, लेकिन जिले में नशे का नाश करने की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। नशे के कारण होने वाली इन घटनाओं में सिर्फ नसेड़ी या छोटे-मोटे तस्कर ही पुलिस अब तक पकड़ पाई है। यानी नशे से हो रही मौतों के बावजूद पुलिस अब तक अपनी कार्रवाई के नाम पर ऊँट पर बैठ कर बकरीया ही चरा रही है। जबकि होना तो यह चाहिए था कि नशे के इस समंदर की बड़ी मछली का शिकार पुलिस करती और जिले के युवाओं व भविष्य को नशे के समंदर में डूबने से बचाती।

मगर कहते हैं न कि उम्मीद पर दुनिया कायम है तो अब भी पुलिस से यही उम्मीद है कि वह इस विषय को गंभीरता से लेते हुए नशे के इस कारोबार में संलिप्त बड़े तस्करों तक पहुंचकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। अगर पुलिस इस उम्मीद पर खरी नहीं उतरती है तो जिले के युवा वर्ग को नशे के नाश से कोई नहीं बचा पाएगा। जिस युवा पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं वहीं युवा पीढ़ी नशे के समंदर में गर्क होकर जिले के अस्तित्व को खत्म करने की कगार पर पहुंचा देगी।

गूँज असर: विधायक ने तय की धरने की तारीख

झाबुआ मार्ग पर टूटे पुल निर्माण के लिए धरने की धमकी देकर गायब हुए थे विधायक मैडा



माही की गूँज, रायपुरिया।

माही की गूँज अखबार के पिछले अंक में 'हथेली में हाथी दिखा गए विधायक साहब, विभाग ने मोरम बिछा कर दिया ऊँट के मुँह में जीरे वाला काम' शीर्षक के साथ प्रकाशित समाचार के बाद गूँज की खबर का असर हुआ है और विधायक अब धरने की तारीख तय कर लगभग तीन वर्षों से चल रही रायपुरिया-झाबुआ मार्ग पर टूटे पुल निर्माण करवाने की बात कही है। विधायक वालसिंह मैडा ने बताया कि, 12 जुलाई सोमवार को 11 बजे एक दिन का धरना प्रदर्शन पुल निर्माण की माँग को लेकर किया जाएगा, यदि जिम्मेदारी की और से आश्वासन मिलता है तो उस तिथि तक इंतजार करेंगे वरना आगे की योजना बनाकर फिर से प्रदर्शन करेंगे।

दरसल झाबुआ-रायपुरिया मार्ग पर पुल श्रतिग्रस्त हुए करिबन तीन वर्ष होने को आए हैं लेकिन अभी तक पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसको लेकर पेटलावद विधानसभा के विधायक वालसिंह मैडा ने कुछ समय पहले प्रशासन को चुनौती दी थी, अगर एक सप्ताह में पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो मैं धरने पर बैठूंगा। जिसको लेकर बुधवार को विधायक वालसिंह मैडा ने जानकारी देते हुए बताया कि, 12 जुलाई को वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें पेटलावद क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहने की बात कही है।

बता दें कि, लोक निर्माण विभाग की लापरवाही की वजह से उक्त स्थान दुर्घटना क्षेत्र में तब्दील गया है और यहां वाहन दुर्घटना में लोगों की मौत तक हो चुकी है व कई लोग घायल भी हो चुके हैं। अब विधायक के प्रयासों के बाद प्रशासन और भाजपा सरकार जागती है या नहीं ये देखना होगा और ये भी देखना होगा कि, विधायक मैडा जनता के हित के लिए मैदान में उतरते हैं या फिर केवल राजनीति चमकाते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा जनजाति समाज को वनों पर अधिकार देने की पहल का वनवासी कल्याण परिषद ने किया स्वागत

माही की गूँज, झाबुआ। जनजाति समाज को वनों पर अधिकार देने हेतु केंद्र सरकार ने पहल कर जनजाति एवं वन मंत्रालय की संयुक्त गाइड लाइन जारी की गई है। जिसके अनुसार अब ग्राम सभा को प्रबंधन के अधिकार देने की मांग पूर्ण की गई है। उक्त मांग पूर्ण होने पर वनवासी कल्याण परिषद ने केंद्र सरकार का इसे स्वागत योग्य कदम बताने हुए कई व्यक्त किया है।

केंद्रीय मंत्री, जनजातीय मंत्री एवं केंद्र सरकार का वनवासी कल्याण परिषद के झाबुआ जिला संगठन मंत्री गनपतसिंह मुनिया, युवा प्रमुख अल्केसा मेडा वनवासी प्रमुख झाबुआ हितरक्षक कांजी भूरिया, वनवासी कल्याण परिषद होस्टल अध्यक्ष महेश मुजाल्दे आदि ने आभार व्यक्त करते हुए एक-दूसरे को मिठाई खिलाई।

11 जुलाई से 11 अगस्त तक जनसंख्या स्थिरता माह मनाया जाएगा दम्पति संपर्क पखवाड़ा 27 जून से 10 जुलाई, सेवा प्रदायगी माह 11 जुलाई से 11 अगस्त तक

माही की गूँज, झाबुआ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जेपीएस ठाकुर ने बताया कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों के बीच में बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणामों से अवगत कराना है। आज की परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि हम विकराल रूप ले चुकी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु तुरन्त प्रभावी कदम उठाये। इसके लिये शासन परिवार नियोजन कार्यक्रम योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जनसंख्या को स्थिर करने के लिये चार महत्वपूर्ण कारक ही जिसके बारे में दम

दम्पतियों को एवं अन्य लोगों को जानकारी प्रदान करना है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग एक अरब पच्चीस करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। तेज गति से बढ़ रही जनसंख्या से पर्यावरण को भी नुकसान होने लगा है साथ में बेरोजगारी भी बढ़ने लगी है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई से 11 अगस्त तक जनसंख्या स्थिरता माह मनाया जाएगा। जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से सभी चिन्तित लक्ष्य दम्पतियों से सम्पर्क कर उन्ही परिवार नियोजन के साधनों व संबंधित जानकारी प्रदायगी की जाएगी। जिसमें अपनी पसंद का साधन उपयोग कर सकेंगे। आज की

परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि हम विकराल रूप ले चुकी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु तुरन्त प्रभावी कदम उठाये। कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुये सभी योग्य दम्पतियों को परिवार नियोजन की सेवा फिक्स डे नसबंदी सेवा प्रदान की जाएगी इन्ड्रुक दम्पति नसबंदी करवा सकते हैं। अस्थायी साधन गांव में आषा कार्यक्रमों एवं एनएम से प्राप्त कर सकते हैं तथा सभी प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र एवं सामुदायिक स्वा. केन्द्र में भी उपलब्ध है। पूरे माह नसबंदी की स्थाई सेवा प्रदान करने हेतु सभी विकासखण्ड को निर्देशित किया गया है।

प्रादेशिक ई-चिंतन सत्र का हुआ आयोजन

माही की गूँज, झाबुआ।

केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग व भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित प्रादेशिक ई चिंतन सत्र का जिला भाजपा कार्यालय झाबुआ में आयोजन किया गया। जिला भाजपा मिडिया प्रभारी योगेन्द्र नाहर ने बताया कि ई चिंतन सत्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संघटन महामंत्री शिव प्रकाश द्वारा डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार एवं कार्य विषय पर प्रादेशिक व जिला पदाधिकारियों का

कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया। इस बैठक में प्रमुख रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह नायक, सांसद गुमान सिंह डामोर, प्रदेश मंत्री संगीता विश्वास सोनी, प्रदेश कार्यकर्ताओं सदस्य ओम प्रकाश शर्मा, जिला भाजपा महामंत्री सोमसिंह सोलंकी, जिला उपाध्यक्ष प्रवीण सुराणा, थानेला मंडी के पूर्व अध्यक्ष मनु डामोर, पेटलावद मंडी के पूर्व अध्यक्ष भरत पाटीदार आदि उपस्थित रहे। आई टी सेल प्रभारी अर्पित कटकानी द्वारा ई चिंतन सत्र का कार्यक्रम संचालित किया गया।

खण्ड स्तरीय चयन समिति की बैठक संपन्न

माही की गूँज, झाबुआ। मंगलवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर एलएन गर्ग की अध्यक्षता में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु खण्ड स्तरीय चयन समिति की बैठक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी मेघनगर में संपन्न हुई। मेघनगर परियोजना अंतर्गत ग्राम देमारा पटेल फलिया, बाडीसेरा, गडुली तथा मेघनगर बाफना कॉलोनी वार्ड 3 से प्रत्येक क्षेत्र में चयन कर अन्तिम सूची तैयार की गई है। आंगनवाड़ी के रिक्त पदों के चयन की अन्तिम सूची के विरुद्ध किसी से किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वे दिनांक 16 जुलाई तक कार्यालयीन समय में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।

काव्य गोष्ठी, पुस्तक विमोचन तथा सम्मान समारोह का आयोजन 9 को

माही की गूँज, झाबुआ। माहिम्पति कला मंच तथा राष्ट्रीय कवि संगम की जिला इकाई झाबुआ द्वारा आगामी 9 जुलाई को स्थानीय सिद्धेश्वर कॉलोनी स्थित रोटीरी सदन में काव्य गोष्ठी, पुस्तक विमोचन तथा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माहिम्पति कला मंच के क्षेत्रीय प्रभारी यशवंत भंडारी तथा संस्था जिलाध्यक्ष एमएल फुलपगारे उपस्थित रहेंगे। विशेष अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार मनोज जैन मौजूद रहेंगे। अध्यक्षता राष्ट्रीय कवि संगम के जिलाध्यक्ष प्रवीण सोनी करेंगे।

मीडिया प्रभारी दैलत गोलांनी ने बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद तथा वर्तमान में कोरोना केस पूरी तरह से कम होने के बाद पुनरू साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकारों, कवियों और रचनाकारों को अपनी प्रतुतियों के लिए खुला मंच प्रदान करने हेतु यह कार्यक्रम रखा गया है। काव्य गोष्ठी में साहित्यकार और कविगण बोते कोरोनाकाल में जिले में बने परिदृश्य, वर्तमान हालातों और भविष्य को लेकर भी अपनी-अपनी रचनाओं और कविताओं का पाठ करेंगे। गीत, गजल, देशभक्ति रचनाएं आदि प्रस्तुत करेंगे।

डॉ. गीता दुबे का किया जाएगा सम्मान

कार्यक्रम में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ के सेवानिवृत्त लेखापाल नंदकिशोर पंवार की पुस्तक 'गीत आत्मकथा' का विमोचन होगा। साथ ही पीजी कॉलेज झाबुआ में वर्षों तक सरहनीय सेवाएं वाली वरिष्ठ प्राध्यापक तथा साहित्यकार डॉ. गीता दुबे के सेवानिवृत्ति होने पर दोनों संस्थाओं द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा।

वसोम सैयद विधायक प्रतिनिधि नियुक्त

माही की गूँज, झाबुआ।

विधायक कातिलाल भूरिया ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता की अनुशंसा पर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झाबुआ की जनभागीदारी समिति में अपना प्रतिनिधि युवा कांग्रेस नेता वसोम सैयद को नियुक्त किया है, जो सामान्य जनभागीदारी परिषद की बैठक में विधायक प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा ले सकेंगे। सैयद की नियुक्ति पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रकाश शंका, हेमचंद्र डामोर, गौरव सक्सेना, आशीष भूरिया, विजय भावर, विनय भावर, साबिर फिटवेल, हेमेश बबलू कटारा, विशाल रावैर, शाहसूख खान, इरितयाक शेख, जितेंद्र शाह आदि ने हर्ष व्यक्त करते हुए विधायक भूरिया के प्रति आभार व्यक्त किया है।



13 लाख 10 हजार में से पुलिस के हाथ लगे मात्र 8 लाख 20, आरोपी एक भी हथे नहीं चढ़ा

बैंक में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा मगर जारी प्रेसनोट में चोरी हुई रकम का जिक्र नहीं

बकाया 4 लाख 90 हजार का कोई खुलासा नहीं

माही की गूँज, झाबुआ।

29 जून को शहर की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से 13 लाख 10 हजार रुपये से भरा बैग चोरी हो गया था। सात दिन बाद पुलिस ने मंगलवार को इसका खुलासा किया। पुलिस ने प्रेसवार्ता आयोजित कर बताया कि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से उन्हे कार का पता लगा और वह इस चोरी का खुलासा कर पाई है। कार मालिक सहित वारदात को अंजाम देने वाले तीन लोगों को आरोपित बनाया गया है। इनमें एक नाबालिग भी है। चारों आरोपित पार हैं लेकिन उनके घर से 8 लाख 20 हजार रुपये जब्त हो गए हैं। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपी राजगढ़ जिले के कडिया सांसी गांव के हैं।

29 जून को हुआ कुछ ऐसा था कि देवझिरी आदिम जाति सोसायटी के कर्मचारी किसानों से ऋण वसूली के रुपये

लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पीलीकोटी में जमा करने के लिए पहुंचे थे। वे अपना रुपयों से भरा बैग कार्टर पर रखकर जमा पंजी भर रहे थे। इसी बीच बैग गायब हो गया था। इतनी बड़ी रकम बैंक से गायब होते ही हड़बड़ी मच गई थी। जिसके बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने बैंक व शहर के सीसीटीवी खंगलने शुरू किए और घटना के सात दिन बाद वारदात का खुलासा भी कर दिया।

झाबुआ पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि कार से नाबालिग व दो आरोपित झाबुआ आए। कार चर्च कालोनी के पास खड़ी कर दी गई। फिर एक ऑटो से तीनों राजगढ़ आए। यहां से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में आकर वहां की तमाम गतिविधियों पर नजर रखने लगे। मौका देखते ही नाबालिग आरोपी बैंक के अंदर गया और 13 लाख 10 हजार का बैग उठाकर रफ्तार से भागा। बैंक के बाहर मौजूद दोनों साथियों के साथ वे फिर राजगढ़ गए और वहां से ऑटो किराए पर



लेकर जिला अस्पताल के सामने उतर गए। यहां से वे अपनी कार में बैठकर रवाना हो गए। पुलिस ने मुखबिरों को एकदम से अलर्ट कर दिया। थाना प्रभारी सुरेंद्रसिंह गडरिया के साथ एक टीम राजगढ़ ब्यावरा जिले में भेजी गई और स्थानीय पुलिस की मदद ली गई। इस बीच यह जानकारी मिली कि राजगढ़ ब्यावरा जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कडिया सासी क्षेत्र के लोग इसी तरह से बैंकों में जाकर वारदात करते हैं। दो दर्जन से अधिक लोगों को पूछताछ करने के बाद आरोपितों की पुष्टा पहचान की गई

और उनके घर पर दबिश दी गई। आरोपित पार हो गए लेकिन उनके घर से छान-बीन करने पर 8 लाख 20 हजार रुपये जब्त किए गए हैं। वारदात करने वाले नाबालिग व उसके दो साथी सावन उर्फसावंत, चप्पू पुत्र भारतसिंह सिसौदिया, काबारा पुत्र बंशीलालसिंह सिसौदिया दोनों निवासी कडिया सासी के अलावा कार मालिक रानीबाई पति दिलीपसिंह निवासी ग्राम जाट खेड़ी को भी आरोपित बनाया गया है। चारों आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए 10-10 हजार रुपये ईनाम की घोषणा की गई है। पुलिस ने प्रेसवार्ता व प्रेसनोट जारी करते हुए घटना का खुलासा तो कर दिया लेकिन यहां यह नहीं बताया गया कि चोरी हुई रकम कुल कितने रुपये थी। पुरी प्रेसवार्ता में बरामद किए गए 8 लाख 20 हजार का जिक्र ही होता रहा। जबकि इस घटना में 13 लाख 10 हजार रुपये चोरी होने की बात कही जा रहा है। अगर चोरी 13 लाख 10 की थी तो पुलिस ने बकाया 4 लाख 90

हजार का खुलासा क्यों नहीं किया? या फिर यह माना जा रहा है कि चोरी भी 8 लाख 20 हजार की ही हुई थी। हालांकि पुलिस यह दावा कर रही है कि 8 लाख 20 रुपये की यह रकम उसने आरोपियों के घर से बरामद की है। चोरों के ठिकाने तक पहुंचने के बाद पुलिस को सिर्फ चोरी गई रकम का कुछ हिस्सा ही हाथ लगा। जबकि घटना को अंजाम देने वाला एक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्तार में नहीं आया। सवाल यह भी उठता है कि जब आरोपी पुलिस के पहुंचने से पहले ही पार हो गए थे तो क्या उन्हे पता था कि पुलिस दबिश देगी। अगर ऐसा था तो वे चोरी की गई रकम अपने साथ क्यों नहीं ले गए। अगर इसका यह तर्क है कि बाकी के 4 लाख 90 हजार चोर अपने साथ ले गए। तो फिर वह बरामद की गई 8 लाख 20 हजार की रकम क्यों छोड़ गए। अभी घटना के सारे आरोपी पार हैं, अगर यह पकड़े नहीं गए तो बरामद किए गए 8 लाख 20 हजार का जिक्र ही होता रहा। जबकि इस घटना में 13 लाख 10 हजार रुपये चोरी होने की बात कही जा रहा है। अगर चोरी 13 लाख 10 की थी तो पुलिस ने बकाया 4 लाख 90

संपादकीय

सरकार की छवि सुधारने को नेतृत्व परिवर्तन



उत्तराखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में भारी जीत

दर्ज करने वाली भाजपा को चार माह में यदि दो मुख्यमंत्री बदलने पड़े तो जाहिर है कि, पार्टी में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। राज्य बनने के दो दशक के दौरान यदि ग्यारहवें मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई तो यह राजनीतिक अस्थिरता का ही पर्याय है। पिछले चुनाव में जनता ने 57 सीटें देकर पार्टी में पूरा विश्वास जताया था, लेकिन पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आया जो पूरे पांच वर्ष तक राज्य को कुशल नेतृत्व दे सकता। हालांकि, राज्य में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे की वजह जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 151 के चलते उत्पन्न संवैधानिक संकट को बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि, इसके मूल में पार्टी का असंतोष ही है। बताते हैं कि, पार्टी के अंदरूनी सर्वेक्षण में यह बात सामने आई थी कि तीरथ सिंह रावत 2022 में होने वाले चुनाव में पार्टी के खेवनेहार साबित नहीं हो सकते। यही वजह है कि, कुल 114 दिन के कार्यकाल के बाद तीरथ सिंह रावत ने बीते शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। वैसे भी रावत अपने विवादित बयानों के कारण खासे सुर्खियों में रहे। महिलाओं की फटी जीन्स पर की गई उनकी टिप्पणी की खासी आलोचना हुई। फिर भारत के अमेरिका के अधीन रहने के बयान पर पार्टी की किरकिरी हुई। कुंभ मेले के आयोजन व कोरोना संकट पर उनके विवादित बयान सुर्खियां बनते रहे। सवाल यह है कि, ग्यारहवें मुख्यमंत्री बनने वाले युवा पुष्कर सिंह धामी पार्टी की साख को संवारते हुए आसन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे? उन्हें पार्टी की छवि संवारनी है और खुद को भी साबित करना है। उनके पास किसी मंत्री पद का अनुभव भी नहीं है। साथ ही पार्टी के दिग्गज नेताओं को साथ लेकर भी चलना है जो उनके मुख्यमंत्री बनने की घोषणा के बाद तेवर दिखा रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी रहे धामी भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष व विद्यार्थी परिषद के विभिन्न पदों पर रहे हैं।

बहरहाल, राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के संकट ने उत्तराखंड में विपक्षी कांग्रेस को हमलावर होने का मौका दे दिया है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि, राज्य में डबल इंजन वाली सरकार का फायदा राज्य की जनता को नहीं मिला और पार्टी अपने चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाई है। निःसंदेह, जब राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने बाकी हैं, पुष्कर सिंह धामी के लिए कई चुनौतियां सामने खड़ी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि, धामी को मुख्यमंत्री के रूप में कांटों का ताज मिला है। राज्य में भाजपा सरकार के कामकाज पर कई प्रश्नचिह्न हैं। जहां उन्हें एक ओर पार्टी के असंतुष्टों को साथ लेकर चलना है, वहीं सरकार की छवि सुधारनी है ताकि 2022 के समर में वे जनता से अधिकार से वोट मांग सकें। उनके पास समय कम है और काम ज्यादा है। भाजपा की कोशिश है कि, उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड में भी फिर से उसकी सरकार लौटे। उत्तर प्रदेश में हालिया जिला पंचायत चुनावों के परिणामों से जहां भाजपा उत्साहित है, वहीं उत्तराखंड की स्थिति उसकी चिंता बढ़ाने वाली है। मौजूदा बदलाव उसी चिंता का परिचायक है। दरअसल, पार्टी की दिक्रत यह है कि, पश्चिम बंगाल की तरह उसके पास उत्तराखंड में कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है, जिसके चलते असंतोष के सुर उभरते हैं, जिसका समाधान पार्टी नेतृत्व परिवर्तन के रूप में देखती है। कमाबेश यही स्थिति कांग्रेस की भी रही है, जिसने 2013 की केदारनाथ आपदा में सरकार की नाकामयाबी के बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को बदलकर हरीश रावत को सरकार की बागडोर सौंपी थी। बहरहाल, आने वाला वक्त बताएगा कि, राज्य में नेतृत्व परिवर्तन पार्टी के भविष्य के लिए कितना कारगर साबित होता है। चुनाव में भाजपा के लिए परंपरागत विरोधी पार्टी कांग्रेस तो मौजूद है, लेकिन इस बार राज्य में आम आदमी पार्टी की चुनौती का भी उसे सामना करना पड़ेगा क्योंकि आप ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है।

कोरोना काल में अदालत

कोविड-19 के दौरान देश की अदालतों में प्रत्यक्ष रूप से मुकदमों की सुनवाई लगभग बंद है। अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक मुकदमों की सुनवाई कर रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था का यह लाभ है कि, अदालत परिसर में अपने मुकदमे का इंतजार करने की बजाए वकील अपने चैंबर, घर, कार्यालय या किसी अन्य उचित स्थान से बहस कर सकते हैं। इस दौरान वकीलों से अपेक्षा की जाती है कि, वे अधिवक्ता कानून में प्रदत्त ड्रेस कोड और शिष्टाचार का पालन करेंगे। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि, वकीलों में पेशेगत गरिमा बनाए रखने, ड्रेस कोड का पालन करने और शिष्टाचार में चूक हो रही है। ऐसा करने वालों में डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता भी शामिल हैं। यही वजह है कि, उच्चतम न्यायालय से लेकर निचली अदालत तक के पीठासीन न्यायाधीशों को अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसा आचरण करने वाले वकीलों को फटकार ही नहीं लगायी पड़ी है बल्कि उन पर जुर्माना भी किया है।

महामारी काल में न्यायपालिका ने वकीलों को ड्रेस कोड में मामूली-सी रियायत प्रदान की थी। न्यायपालिका को अपेक्षा थी कि, वकील मुकदमों में पेश होते वक्त अपने पेशे के अनुरूप गरिमामय परिधान में होंगे और शिष्टाचार का ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ वकील न तो गरिमामय पोशाक में होते हैं और न ही वे अदालत के सम्मान के अनुरूप आचरण कर रहे होते हैं। वकीलों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय की कार्यवाही के दौरान किसी प्रकार का शोरगुल या व्यवधान नहीं हो। लेकिन कई मामलों में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वकील सड़क के किनारे, पार्क में या फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए अथवा स्क्रूटर पर यात्रा करते हुए ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहस करते नजर आए।

उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 13 मई, 2020 को वकीलों के लिए ड्रेस कोड में कुछ राहत प्रदान की थी। न्यायालय ने वकीलों को काला गाउन नहीं पहनने की छूट दी थी लेकिन उनके लिए अगले आदेश तक या मौजूदा चिकित्सा अनिवार्यता रहने तक सफेद शर्ट-सलवार-कमीज-सफेद साड़ी पहने और गले में वकीलों का सफेद बैंड बांधना अनिवार्य था। इस राहत का तात्पर्य यह नहीं था कि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान न्यायाधीश के समक्ष पेश होते वक्त वकील रंग-बिरंगे कपड़े पहने नजर आए। कई बार वकील रंगीन कपड़े पहने हैं, या फिर सिर्फ बनियान ही पहने हैं या बिस्तर में हैं। चूंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता है और इसी वजह से यह नजारे न्यायाधीशों की नजर में आ गए जिस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति की और ऐसा आचरण करने वाले वकीलों को फटकार भी लगाई।

इस तरह का अजीब मामला पिछले वर्ष उच्चतम न्यायालय में भी न्यायाधीशों के सामने आ गया था, जिसमें संबंधित वकील टी-शर्ट पहनकर कार्यवाही में शामिल हुए थे। न्यायालय को उस वकील का यह आचरण नागवार लगा और उसने उन्हें इस आचरण के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि, वर्युअल सुनवाई में भी कम से कम शिष्टाचार बनाए रखें। राजस्थान उच्च न्यायालय में तो एक वकील बनियान पहन कर ही पेश हो गए थे जिस पर पीठासीन न्यायाधीश ने नाराजगी व्यक्त की थी।

यही स्थिति उड़ीसा उच्च न्यायालय में देखने में आई जहां एक वकील बहस के समय अपना नेक बैंड नहीं बांधे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि, अदालत ने उन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी बार को ऐसे असावधानी नहीं बरतने की हिदायत दी और कहा कि, एक मामले में वर्युअल सुनवाई के दौरान एक वकील की कार में पीछे एक अन्य व्यक्ति भी बैठा हुआ था। इस तरह का आचरण अदालती कार्यवाही का अनादर है। न्यायपालिका इस समय बहुत ही विषम परिस्थितियों में अदालती कामकाज निपटा रही है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का ही अभिन्न अंग बार के सदस्य वकीलों से अपेक्षा की जाती है कि वे महामारी के इस दौर में स्थिति की गंभीरता को समझेंगे और सुचारु ढंग से अदालतों की वर्युअल कार्यवाही के संचालन में सहयोग करेंगे।



अनु भटनगर

वोट की फसल

जिला पंचायत चुनाव को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। जिसमें सदस्य संख्या में पिछड़ने के बाद जिलों पर भाजपा का दबदबा बन गया। इस लिहाज से यह नहीं कहा जा सकता कि, जीता कौन। क्योंकि सपा और भाजपा दोनों ने ही दमदारी से खेल दिखाया है। अब अगले वर्ष फाइनल कौन जीतेगा, यह पता चलने में समय है, लेकिन टीम तैयार करने की कवायद अभी से शुरू हो गई है। भाजपा की तैयारी पूरी है। अगर कुछ बड़ा नहीं हुआ तो पार्टी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव में जाएगी। वहीं विपक्षी खेमा अपनी टीम को धार देने में जुटा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद सजय सिंह से मुलाकात कर चुके हैं। असदुद्दीन औवैसी के साथ ओमप्रकाश राजभर की लगातार बैठकें हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत कर रही है। इसके साथ ही निपाद पार्टी समेत बिहार में अति पिछड़ों की विकासशील इंसान पार्टी भी उत्तर प्रदेश में इस समुदाय की राजनीति करने वालों के लिए थोड़ी अहमजता पैदा कर रही है। कुल मिलाकर राज्य में इस तरह की राजनीतिक उत्पत्क इस बात का संकेत है कि, आने वाले विधानसभा के चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। यूपी में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए आस-पास के राज्यों की पार्टियों ने अपनी जड़ों को जमाने के लिए पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी है। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि, इस बार कैसे भी कर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। इसके लिए कई दलों ने एक साथ मिलकर गठबंधन की घोषणा भी कर दी है।

उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की जो मुलाकातें हो रही हैं उससे यह नए गठबंधन के रास्ते खुलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। दोनों नेताओं की

यह पहली मुलाकात नहीं थी इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि, मामला गठबंधन की राह पर चल निकला है। हालांकि आप सांसद संजय सिंह ने इस मुलाकात को महज आपसी सौहार्द की मुलाकात तक रखने की बात की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके अलग मायने निकाले जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि, जिस तरह सपा और आप, ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ खड़े होते हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि, टीएमसी भी इस गठबंधन में शामिल हो सकती है। विश्लेषकों के मुताबिक तीनों का गठबंधन यूपी की मुस्लिम बाहुल्य

आबादी को बहुत बेहतर तरीके से साथ जोड़ने की ताकत रखता है। छोटे-छोटे राजनीतिक दलों के आपस में गठबंधन के साथ प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह अकेले ही चुनाव लड़ने के मूड में हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि, वह आक्रामक रूप से ही चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। चूंकि कुछ अहम दलों की राजनीतिक बिनात बिछ चुकी है लेकिन उसमें कांग्रेस की कोई संभावना नहीं दिख रही। बसपा ने एलान कर दिया है कि, वह कोई गठबंधन नहीं करेगी तो, कांग्रेस उससे भी नहीं जुड़ सकती। सपा और कांग्रेस का पिछला अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा इसलिए इसकी संभावना भी न के बराबर है। इस बार भी उत्तर प्रदेश में जातिगत वोटों के आधार पर ज्यादा बंटवारे की संभावनाएं नजर आ रही हैं। यही वजह है कि, ज्यादा से ज्यादा छोटे-छोटे समुदायों में अपनी पकड़ रखने वाली राजनीतिक पार्टियां इस बार प्रमुख दलों के साथ मिलकर चुनाव की रंगत को बदलना चाहती हैं।



सिद्धार्थ शंकर

बिटकॉइन के खतरे और प्रतिबंध की तार्किकता

किसी समय इंटरनेट में एक अमीर थे रॉसचाइल्ड। इनकी कई देशों में व्यापारिक शाखाएं थी। यदि किसी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में रकम पहुंचानी होती थी तो वह ट्रांसफर रॉसचाइल्ड के माध्यम से सुरक्षापूर्वक हो जाता था। जैसे मान लीजिए आपको दिखी से मुंबई रकम पहुंचानी है। आपने रॉसचाइल्ड के दिखी दफ्तर में एक लाख चांदी के सिक्के जमा करा दिए। उन्होंने आपको एक लाख सिक्कों की रसीद दे दी। आप मुंबई गए और रॉसचाइल्ड के मुंबई दफ्तर में वह रसीद देकर आपने एक लाख सिक्के प्राप्त कर लिए। इतने सिक्कों को लेकर जाने के इच्छित से आप मुक हो गए। समय क्रम में रॉसचाइल्ड ने देखा कि, उनके लिखे हुए प्रॉमिसरी नोट या रसीद पर लोगों को अपार विश्वास है। उन्होंने स्वयं ही प्रॉमिसरी नोट बनाए और मिली रकम से अपना व्यापार बढ़ाया। जैसे मान लीजिए उन्हें कोई मकान खरीदना था। उन्होंने एक करोड़ सिक्कों का प्रॉमिसरी नोट लिख दिया और मकान के विक्रेता ने उस रसीद को सच्चा मानकर उन्हें मकान बेच दिया। रॉसचाइल्ड द्वारा जारी की गई यह रसीदें अथवा प्रॉमिसरी नोट ही आगे चलकर नकद नोट के रूप में प्रचलित हुए। समय क्रम में सरकारों ने अथवा उनके केंद्रीय बैंकों ने इसी प्रकार के प्रॉमिसरी नोट छापना एवं जारी करना शुरू कर दिया। इन्होंने नोट को नकद नोट कहा जाता है। आप देखेंगे कि, रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोट पर लिखा रहता है, 'मैं धारक को एक सौ रुपये अदा करने का वचन देता हूँ।' ऐसा ही वचन रॉसचाइल्ड ने दिया था, जिससे कि नकद मुद्रा का चलन शुरू हो गया। जाहिर है कि, नोट का प्रचलन इस बात पर टिका हुआ है कि उसे जारी करने वाले पर समाज को विश्वास है अथवा नहीं। इसी विश्वास के आधार पर बिटकॉइन एवं अन्य क्रिप्टोकरंसी का आविष्कार हुआ है। ऐसा समझें कि, सी कम्प्यूटर इंजीनियर एक हॉल में बैठे हैं और उन्होंने एक सुडोकू पहेली को आपस में हल करने की प्रतिस्पर्धा की। जिस इंजीनियर ने उस पहेली को

सर्वप्रथम हल कर दिया, उसके हल की अन्य इंजीनियरों ने जांच की, और सही पाने पर उन्हें एक बिटकॉइन इनाम स्वरूप दे दिया। इन इंजीनियरों ने आपसी लेन-देन इन बिटकॉइन में करना शुरू कर दिया। एक इंजीनियर को दूसरे से कार खरीदनी हो तो उसका पेमेंट दूसरे को बिटकॉइन से कर दिया। यह संभव हुआ चूंकि दोनों इंजीनियरों को उस बिटकॉइन पर भरोसा था। अब इस बिटकॉइन की विश्वसनीयता सिर्फ उन सी कम्प्यूटर इंजीनियरों के बीच है, जिन्होंने उस खेल में भाग लिया था। समय क्रम में ये सी कम्प्यूटर इंजीनियर बढ़कर दस लाख हो गए या एक करोड़ हो गए और तमाम लोगों

अलग-अलग क्रिप्टोकरंसी चालू है। मूल बात यह है कि, बिटकॉइन की विश्वसनीयता इस बात पर टिकी हुई है कि भारी संख्या में लोग इसे मान्यता देते हैं। जबकि इसके आधार में कुछ भी नहीं है। रॉसचाइल्ड अथवा रिजर्व बैंक ने प्रॉमिसरी नोट का भुगतान नहीं किया तो आप उनके घर-दफ्तर पर धरना दे सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन का कोई घर नहीं है। ये एक करोड़ कम्प्यूटर इंजीनियर अलग देशों में रहते हैं और इन्होंने कोई लिखित करार नहीं किया है। बिटकॉइन में तमाम समस्याएं दिखने लगी हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि, आज बिटकॉइन बनाने की बड़ी

फैक्टरियां लग गई हैं। सुडोकू की पहेलियां इतनी जटिल हो गई हैं कि इन्हें हल करना मनुष्य की क्षमता के बाहर हो गया है। उद्यमियों ने बड़े कम्प्यूटर लगा रखे हैं जो इन पहेलियों को हल करते हैं और जब इनका हल हो जाता है तो उन्हें बिटकॉइन का समाज एक बिटकॉइन दे देता है। जिस प्रकार आप दुकान में कम्प्यूटर लगाने में निवेश करते हैं, उसी प्रकार ये उद्यमी बिटकॉइन की पहेलियां हल करने के लिए कम्प्यूटर लगाने में निवेश करते हैं और बिटकॉइन कमाते हैं। यह प्रक्रिया पूर्णतया पर्यावरण के

विरुद्ध है। बड़ी-बड़ी फैक्टरियों में भारी मात्रा में बिजली खर्च होती है, जिससे ये कम्प्यूटर चलाए जाते हैं और इससे किसी प्रकार का जनहित हासिल नहीं होता। दूसरी समस्या अपराध की है। बीते समय में अमेरिका की कॉलोनियल आयल कंपनी के कम्प्यूटरों को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने कॉलोनियल आयल कंपनी को सूचना दी कि वे अमुक रकम बिटकॉइन के रूप में उन्हें पेमेंट करें तब वे उनके कम्प्यूटर से जो मॉलवेयर यानी कि, जो उसमें अवरोध पैदा किया गया था, उसको हटा देंगे। कॉलोनियल आयल कंपनी ने उन्हें लगभग पैंतीस करोड़ रुपए का मुआवजा बिटकॉइन के रूप में दिया, जिससे कि उनके कम्प्यूटर पुनः चालू हो जाएं। इस प्रकार बिटकॉइन जैसी करंसी आज अपराध को बढ़ावा दे रही है क्योंकि इनके ऊपर किसी सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है। बिटकॉइन बनाने वाली फैक्टरी या उसका उद्यमी रूस में है, चीन में है, भारत में है या इंडोनेशिया में, इसकी कोई जांच नहीं होती क्योंकि सारा लेन-देन इंटरनेट पर होता है। इस प्रकार आज अपराधियों द्वारा वसूली बिटकॉइन के माध्यम से की जा रही है। तीसरी समस्या रिस्क की है। बिटकॉइन हाथ का लिखा हुआ या प्रिंटिंग प्रेस का छपा हुआ नोट नहीं होता। यह केवल एक विशाल नंबर होता है जो कि किसी कम्प्यूटर में सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे भी वाक्ये हुए हैं कि, किसी व्यक्ति का कम्प्यूटर क्रैश कर गया और उसमें रखा हुआ बिटकॉइन का नंबर पूर्णतया पहुंच के बाहर हो गया। उन्हें उस बिटकॉइन का घाटा लगा गया। इसलिए बिटकॉइन का लाभ शून्य है और हानि पर्यावरण, अपराध और रिस्क तीनों की है। इन्होंने समस्याओं को देखते हुए रिजर्व बैंक ने दो वर्ष पहले अपने देश में बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगा दिया था। बीते वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के उस प्रतिबंध को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसलिए वर्तमान में देश में बिटकॉइन का व्यापार कानूनी ढंग से किया जा सकता है। लेकिन सरकार को नया कानून लाकर इसे प्रतिबंधित करने पर विचार करना चाहिए एवं सुप्रीम कोर्ट को इसके नुकसानों को समझना चाहिए, जिससे यह हानिप्रद व्यवस्था समाप्त की जा सके।



को इस प्रकार बिटकॉइन पर विश्वास हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे रॉसचाइल्ड द्वारा जारी किए गए प्रॉमिसरी नोट पर जनता को विश्वास हो गया था। आज विश्व में इस प्रकार की तमाम क्रिप्टोकरंसी हैं। बिटकॉइन को एक करोड़ कम्प्यूटर इंजीनियर मान्यता देते हैं तो एथेरियम को मान लीजिए पचास लाख कम्प्यूटर इंजीनियर मान्यता देते हैं। जितनी मान्यता है, उतना ही प्रचलन है। इस प्रकार तमाम लोगों ने अपनी-अपनी क्रिप्टोकरंसी बना रखी है। आज विश्व में लगभग पंद्रह सौ

फैक्टरियां लग गई हैं। सुडोकू की पहेलियां इतनी जटिल हो गई हैं कि इन्हें हल करना मनुष्य की क्षमता के बाहर हो गया है। उद्यमियों ने बड़े कम्प्यूटर लगा रखे हैं जो इन पहेलियों को हल करते हैं और जब इनका हल हो जाता है तो उन्हें बिटकॉइन का समाज एक बिटकॉइन दे देता है। जिस प्रकार आप दुकान में कम्प्यूटर लगाने में निवेश करते हैं, उसी प्रकार ये उद्यमी बिटकॉइन की पहेलियां हल करने के लिए कम्प्यूटर लगाने में निवेश करते हैं और बिटकॉइन कमाते हैं। यह प्रक्रिया पूर्णतया पर्यावरण के

न्यूज़ ब्रीफ

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजनान्तर्गत जिले में 15 बच्चों लाभान्वित

माही की गूंज, अलीराजपुर। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना अंतर्गत जिले के 15 पात्र बच्चों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। इन बच्चों को योजनान्तर्गत शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा की सुविधा प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में लागू की गई 'मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत जिले में अलग-अलग विकासखंडों के 15 बच्चों को उक्त योजना के तहत लाभ दिया गया है। उक्त जानकारी देते हुए डीपीओ आईसीडीएस श्रीमती शिवकली वरवडे एवं सहायक संचालक आईसीडीएस श्री विजयसिंह सोलंकी ने बताया उक्त योजनान्तर्गत 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 की अवधि में कोविड-19 महामारी में ऐसे बच्चे जिनके माता एवं पिता दोनों की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो। योजना के तहत जिले में 15 बच्चों को योजना से लाभान्वित किया गया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ली लोक अदालत के संबंध में बैठक

माही की गूंज, पेटलावद। माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर एवं श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिस संबंध में तहसील पेटलावद के एवं रायपुरिया एवं अभिभाषक की मीटिंग ली जाकर मीटिंग में नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग आयोजन के समय न्यायालय पेटलावद में जे.सी.राठौर अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति पेटलावद, संजोव कटारे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, राजेन्द्र बर्मन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, विनोद पुरोहित बार एसोसिएशन अध्यक्ष, अपर लोक अभियोजक/लोक अभियोजक अधिकारी, समस्त अभिभाषकगण न्यायालय पेटलावद एवं न्यायालय के समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण उपस्थित थे।

सौ वर्षीय स्वतंत्रता सैनानी ने भी करवाया वैक्सीनेशन

माही की गूंज, बड़वानी। जिले में चल रहे वैक्सीनेशन महा अभियान दिनों-दिन नई उचाईयों पर पहुंचता जा रहा है, जहाँ युवा वैक्सीनेशन करवाकर आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, वहीं शतायु के हो चुके लोग भी अपना वैक्सीनेशन करवाकर लोगों को अधिक से अधिक संख्या में अपना वैक्सीनेशन करवाने की प्रेरणा दे रहे हैं। बुधवार को शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के टीकाकरण केन्द्र पर सौ वर्षीय स्वतंत्रता सैनानी श्री नारायणजी चवे ने भी पहुंचकर अपना वैक्सीनेशन का दूसरा टीका लगावाया है। स्वतंत्रता सैनानी की शतायु के मददेनजर केन्द्र टीकाकरण कर रही सिस्टर श्रीमती सुषमा वाजपेयी ने भी केन्द्र से बाहर जाकर आटो रिक्शा में ही श्री चौबे का टीकाकरण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

आनलाईन ओलम्पिक री ज प्रतियोगिता का आयोजन 15 को

माही की गूंज, झाबुआ। टोक्यो में 23 जुलाई से प्रारंभ होने वाले 32 वें ओलम्पिक खेल को लेकर देश-प्रदेश के खिलाड़ियों में उत्साह है। हमारे देश से ओलम्पिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों तथा ओलम्पिक खेल से संबंधित जानकारी सभी खिलाड़ियों को हो, इस उद्देश्य से खेल और युवा कल्याण विभाग मप्र के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में आनलाईन 'ओलम्पिक क्रिज 2021' का आयोजन 15 जुलाई को किया जा रहा है।

आनलाईन ओलम्पिक क्रिज प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों के लिय उम्र या जाति का कोई बंधन नहीं है, ना ही किसी प्रकार का शुल्क है। यह प्रतियोगिता पूर्णतः निःशुल्क आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी को अपना पंजीयन 12 जुलाई तक कार्यालयीन समय में खेल और युवा कल्याण विभाग झाबुआ में करवाना अनिवार्य है। पंजीयन के लिए प्रतिभागी का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, आधार कार्ड नम्बर, मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आईडी उपलब्ध कराना होगा। पंजीयन होने के उपरान्त संबंधित प्रतिभागी के मोबाईल नम्बर पर एक लिंक भेजी जाएगी तथा आनलाईन परीक्षा की लिंक भी संबंधित मोबाईल नम्बर पर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों को विभाग की ओर से ई-सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। आनलाईन ओलम्पिक क्रिज प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी अपना पंजीयन 12 जुलाई तक कार्यालयीन समय में करवा सकते हैं।

74 दिवस का मध्यान्ह भोजन जारी किया गया

माही की गूंज, झाबुआ। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिद्धार्थ जैन के मार्गदर्शन में माह दिसम्बर, जनवरी, फरवरी का कुल 74 दिवस हेतु कुल विद्यालय 2411 के कुल विद्यार्थी 183666 हेतु 1520.15 मिट्रीक टन जारी किया गया। जिसका वितरण कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए बीआरसी, स्वयं सहायता समूहों, शिक्षकों व रसोयियों के द्वारा 100 प्रतिशत वितरण किया जा चुका है, इसी के साथ छात्र-छात्राओं को पर्यावरण के ज्ञान मिट्टी, पौधों की जानकारी बागवानी आदि हेतु कुल 80 शालाओं में मां की बगिया, किचिन गार्डन हेतु चार लाख राशि जारी की गई। जैन के मार्गदर्शन में एमआईएस भी 97 प्रतिशत पूर्ण होने तथा किचिन शेड स्वीकृत कुल 8 को भी पूर्ण होने से मध्यान्ह भोजन मोसन अंक तालिका में ए प्रेड प्राप्त है।

माही की गूंज में प्रकाशित समाचार व शिकायत के बाद जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के डंपर अवैध खनन व परिवहन करते पकड़े

तहसीलदार ने इस कार्रवाई में भी कर ली सांट-गांट

माही की गूंज, खवास।

कहते हैं 'चोर चोरी से जाए पर हेरा-फेरी से न जाए' यह बात सफेद पोशधारी व थांदला तहसीलदार ने सिद्ध कर दी, पिछले दिनों मादलदा के समीप थांदला तहसीलदार ने भारीभरकम मशीन से खुदाई कर करोड़ों मेट्रिक टन का अवैध रूप से मोरम खुदाई कर परिवहन करने वाले 8-वें लाइन का कार्य करने वाली जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी के पांच डंपर को तहसीलदार थांदला ने पकड़कर खवासा चौकी में सुपुर्द किए।

कंपनी के विरुद्ध न कोई देखने वाला था, न कोई कार्रवाई करने वाला। 18 फरवरी को माही की गूंज में 'आम करे तो गुनाह खास करे तो बेगुनाह- शीर्षक के साथ समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें थांदला तहसीलदार शक्ति सिंह शिकायत के बाद भामल-मादलदा मार्ग पर जहां जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी के कर्मचारी अवैध रूप से मोरम का खनन कर रहे थे और मौके पर दो पोकलेन मशीन व कई डंपर मिलने के बाद भी किस तरह से साहब ने कार्रवाई नहीं की, का खुलासा किया था। वहीं 4 मार्च को 'जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट उर्फ मनमानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी गलत करे वो सही, बाकी करे तो गलत' के शीर्षक के साथ गूंज ने समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें बिना परमिशन के सिंचाई तालाब से अपने ट्रैक्टरों से पानी भर ले

जा रहे थे, शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई करने नहीं पहुंचे तो ग्रामीणों ने अपने बलबूते पर एकत्रित होकर जीआर इंफ्रा कंपनी व उसके पीटी कॉन्ट्रैक्टर को पानी ले जाने से रोका का खुलासा किया था।

जिसके बाद भी किसी भी अधिकारी ने क्षेत्र में जीआर इंफ्रा कंपनी द्वारा अवैध खनन पर किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। माही की गूंज में समाचार प्रकाशित होने पर आमजन सक्रिय हुए और पिछले सप्ताह ऊपरी स्तर तक शिकायत होने पर तहसीलदार साहब मदलदा पंचायत के कड़ीकुआं में कार्रवाई करने पहुंचे, जहां से भी भारी भरकम मशीनों से अवैध मोरम की खुदाई कर

जा रही थी, शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई करने नहीं पहुंचे तो ग्रामीणों ने अपने बलबूते पर एकत्रित होकर जीआर इंफ्रा कंपनी व उसके पीटी कॉन्ट्रैक्टर को पानी ले जाने से रोका का खुलासा किया था।

जिसके बाद भी किसी भी अधिकारी ने क्षेत्र में जीआर इंफ्रा कंपनी द्वारा अवैध खनन पर किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। माही की गूंज में समाचार प्रकाशित होने पर आमजन सक्रिय हुए और पिछले सप्ताह ऊपरी स्तर तक शिकायत होने पर तहसीलदार साहब मदलदा पंचायत के कड़ीकुआं में कार्रवाई करने पहुंचे, जहां से भी भारी भरकम मशीनों से अवैध मोरम की खुदाई कर



ओपन जिम का विधायक मुकेश पटेल ने किया शुभारंभ



माही की गूंज, आलीराजपुर।

शहर के प्रसिद्ध फतेह क्लब मैदान पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित ओपन जिम का शुभारंभ क्षेत्र विधायक मुकेश पटेल ने किया। इस दौरान फतेह क्लब मैदान पर बच्चे, युवा और बुजुर्गों ने ओपन जिम के विभिन्न उपकरणों पर व्यायाम किया। विधायक पटेल ने शहरवासियों को ओपन जिम की सौगात

को देखकर और रखरखाव पर संबंधित विभाग द्वारा नियमित रूप से ध्यान रखा जाए और समय-समय पर इन मशीनों का मेंटनेंस करवाया जाए। जिससे लंबे समय उक्त व्यायाम की मशीनें सुचारू रूप से चलती रहे। शुभारंभ के पश्चात बड़ी संख्या में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने ओपन जिम की मशीनों पर व्यायाम किया।

इस दौरान जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष ओम राठौर, श्याम राठौर सेन्डी, अजय सोनी, रितेश नवाल, कैलाश राठौड़ सहित बच्चे, युवा और वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे। उक्त ओपन जिम विधायक मुकेश पटेल की अनुशंसा पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित करवाया गया है। गौरतलब है कि इस संबंध में विधायक पटेल ने कुछ माह पूर्व खेल एवं युवा कल्याण विभाग को शहर के फतेह क्लब ग्राउंड, जिला खेल परिसर,

शालाओं में स्थापित ओपन जिम में लेग प्रेस, आर्म एंड सोल्डर व्हील, डबल क्रास वाकर, एलेटीकल एक्सरसाइजर, रिफ अप स्टेशन, एक्सरसाइजिंग बार, चिन अप बार, आर्म व्हील, रोविंग मशीन, नो हिप रीज और टॉक्सिड मशीनें स्थापित की गई है। इस दौरान विधायक पटेल ने बच्चों को बिरिस्कट वितरित किए।

ओपन जिम में ये मशीनें हुई स्थापित

फतेह क्लब में स्थापित ओपन जिम में लेग प्रेस, आर्म एंड सोल्डर व्हील, डबल क्रास वाकर, एलेटीकल एक्सरसाइजर, रिफ अप स्टेशन, एक्सरसाइजिंग बार, चिन अप बार, आर्म व्हील, रोविंग मशीन, नो हिप रीज और टॉक्सिड मशीनें स्थापित की गई है। इस दौरान विधायक पटेल ने बच्चों को बिरिस्कट वितरित किए।

नगर परिषद ने अतिक्रमण के नाम पर उठा लिया सार्वजनिक प्याऊ

माही की गूंज, थांदला।

गर्मी के मौसम या जहां पिने के पानी की व्यवस्था नहीं है वहां आमजन की सुविधाओं के लिए सार्वजनिक प्याऊ की व्यवस्था स्थानीय नागरिकों द्वारा आमतौर पर की जाती है, जिससे भीषण गर्मी या अन्य मौसम में भी आमजन पानी पाने में इस्तेमाल करते हैं। विडम्बना तब उत्पन्न होती है जब आमजन की सुविधाओं का ध्यान रखने वाली नगर परिषद ही ऐसे सार्वजनिक प्याऊ को अतिक्रमण में बताने उठा ले जाती है। लेकिन नगर में शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण पर

उनकी नजर नहीं पड़ती है। क्या ये ही नगर परिषद का कर्तव्य है कि जिस प्याऊ से आमजन को सुविधा हो रही थी उसे ही उठा लिया जाए!



नगर के महात्मा गांधी मार्ग पर बावड़ी मंदिर के बाहर नगर के युवाओं के आर्मीस ग्रुप द्वारा विगत 25 वर्षों से अधिक समय से सड़क से करीब 20 फीट की दूरी पर सार्वजनिक प्याऊ का संचालन किया जा रहा था। उक्त प्याऊ पर भीषण गर्मी में राहगीर, भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में आने वाले ग्राहक, मंदिर में

आने वाले दर्शनार्थी शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। जिसे नगर परिषद ने अतिक्रमण के नाम पर उठवा लिया। मामले में प्रभारी सीएमओ नगर परिषद अशोक चौहान ने बताया कि, उक्त प्याऊ से नगर परिषद अध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष को आपत्ति है इस वजह से हटाना पड़ी।

संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन

मुख्य रूप से नियमितीकरण करने की मांग

माही की गूंज, झाबुआ।

संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ की जिला इकाई ने सोमवार को दोपहर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के पद पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम झाबुआ सोहन कनास को सौपा। जिसमें मुख्य मांग में सभी को स्थायीत्व अर्थात नियमितीकरण करने का जिक्र किया गया। ज्ञापन संघ के जिलाध्यक्ष अजयपालसिंह राठौर, जिला सचिव इंदरसिंह सिसौदिया तथा कार्यकारी अध्यक्ष विनोद बैरागी के नेतृत्व में दिया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में विगत 13 वर्षों से लगभग 70 हजार अतिथि शिक्षक अत्यंत अल्प मानदेय में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों के इतने वर्षों से सेवाएं देने के बाद भी भविष्य सुरक्षित करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है। हर वर्ष नई नियुक्ति के कारण अतिथि शिक्षकों में यह डर सदैव बना रहता है कि वह अगले सत्र

में स्कूलों में कार्य कर पाएंगे या नहीं?, आर्थिक संकट के बोझ के चलते ही प्रदेश में करीब 100 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए हैं। जिसके बाद उनके परिवारजनों का पालन-पोषण नामुमकिन हो गया है। अतिथि शिक्षकों के पक्ष में समर्थन देते हुए देश के कई विधायक, मंत्री तथा सांसद की ओर से पत्र लिखा गया है, परन्तु अब तक उनका स्थायीत्वकरण नहीं किया जाना सरकार की तानाशाही व मनमाने रवैये को प्रदर्शित करता है। ज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को 12 माह का सेवाकाल 62 साल तक स्थायी पद तथा मासिक वेतन प्रदान किए जाने, आरटीई का मापदंड पूरा करने वाले अतिथि शिक्षकों को शिक्षकों के पद पर नियोजित किए जाने, अप्रशिक्षित शिक्षकों को ऑपरेशन क्वालिटी या एनआईओएस से प्रशिक्षण करवाया जाने, जो अतिथि शिक्षक 3 सत्र से अधिक सेवा देकर स्थानांतरण या पद पूर्ति होने पर सेवाओं से बाहर हो गए हैं, उन्हें पुनरुत्थान सेवा का अवसर प्रदान करते हुए लाभ दिया जाने, पीएस, एनएस में तत्काल नियुक्ति करने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपते समय अनेक अतिथि शिक्षक मौजूद रहे।

होगा विकास और सौदर्यीकरण, कमिशनर ने पहले दौर की बैठक की

पांच प्रमुख कार्य हैं प्रस्तावित

संभागयुक्त डॉ. शर्मा ने श्रीमंत बाजीराव पेशवा स्मृति प्रतिष्ठान के सदस्यों से उनकी रूपरेखा के बारे में विस्तार से जाना। समिति के सदस्य विवेक भटोरे ने बताया कि यहां इंटरवेंशन सेंटर, नोकाविहार, सैनिक स्कूल, म्यूसियम और 28 फीट की स्टेच्यू बनाना प्रस्तावित है। सैनिक स्कूल में बाजीराव पेशवा की युद्धनीति के अध्ययन पर जोर दिया जाएगा। बाजीराव पेशवा की युद्धनीति को अमेरिका में पढ़ाया जाता है। नौकाविहार से बकावां, गंगातखेड़ी, धारेधर वही म्यूसियम में बाजीराव पेशवा के जन्म और उनके द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में तथा उनके द्वारा नियुक्त सूबेदारों की प्रतिमाएं भी रखी जायेगी। संभागयुक्त डॉ. शर्मा ने कहा कि यहां पहुंचे मार्ग एक बड़ी समस्या है, इसका समाधान सबसे आवश्यक है। इसके लिए टीडीआर स्कीम के तहत कार्य किया जा सकता है। जो आजकल शहरी क्षेत्रों में कामयाब हो रही है। उसी तर्ज पर यहां भी सम्भानाएँ देखी जा सकती है। इसी बात को लेकर एसडीएम श्री अनुकुल जैन ने बताया कि यहाँ आने के लिए गांव से होकर आना पड़ता है। गांव के किसानों के खलिहान की भूमि है जो कुछ लोग देना चाहते और कुछ मना कर रहे हैं। समिति के श्री भटोरे ने कहा कि पूर्व में 28 अप्रैल से 29 अप्रैल तक तीन दिवसीय मेला आयोजित करने

की रूपरेखा बन चुकी है मगर अभी तक संचालन नहीं हो पाया है। चर्चा के बाद संभागयुक्त डॉ. शर्मा ने कहा कि विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए पहले ट्रस्ट बनाये जिसमें गांव के लोग और एसडीएम को शामिल करें। अभी तो प्रारंभिक रूप से जानकारी एकत्रित की गई है। भूमि के अधिग्रहण और कितनी भूमि कहा कहा से ली जा सकती है। इसके अलावा दानदाताओं से भी सहयोग मिल जाता है। इस दौरान कसरतवा द संघ से सीईओ मोहन वासकले और तहसीलदार भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने उन्हें जानकारी देते हुए बताया कि 100 गायों के लिए यह कार्य है। यहां पूर्व से ही निजी रूप से एक गौशाला है। जिसका समिति संचालन करती है। गौशाला निर्माण के बाद एएससीजी द्वारा गौशाला संचालित की जाएगी। मौके पर उपस्थित जिला पंचायत सीईओ गौरव बेनल ने कहा कि शासन द्वारा 20 रुपये प्रति गाय के लिए प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दानदाताओं से भी सहयोग मिल जाता है। इस दौरान कसरतवा द संघ से सीईओ मोहन वासकले और तहसीलदार भी उपस्थित रहे।

मनरेगा से खेल मैदान करे समतल

संभागयुक्त डॉ. शर्मा ने जिला पंचायत सीईओ श्री बेनल को निर्देश दिए कि, महेश्वर में निर्माणाधीन कन्या परिसर में स्थान काफ़ी है। बिल्लिंडा भी बनकर तैयार हो रही है। यहां मैदान को समतल करने के लिए मनरेगा योजना से कार्य करे। ज्ञात हो कि संभागयुक्त डॉ. शर्मा बुधवार को जिले के भ्रमण पर रहे और इसी दौरान वे नवनिर्मित निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां 500 बालिकाओं के लिए परिसर बनाया जा रहा है। संभागयुक्त ने बाउंड्रीवाल का निर्माण भी करने के निर्देश दिए। इस दौरान मंडलेश्वर एसडीएम श्री मिलिंद ढोके, पीआरओ के अधिकारी और जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त श्री जेएस डामोर उपस्थित रहे।

